[Shri K.N. Balagopal]
not raising their voice against the power tariff hike. I am raising this issue now because, at present, the Central Government is responsible for power tariff hike in Delhi. Two days back, the hon. Finance Minister presented, the Budget for Delhi. Delhi is under Central rule. As per the directions of the Supreme Court and the High Court, the C and AG is auditing the power companies in Delhi. It is not a good practice to hike the power tariffs when the C and AG audit of the companies is going on. The Government is saying that the Regulatory Commission is doing that. But, last Friday, the Planning Minister said in this House that the Regulatory Commission, in difficult sectors, requires re-examination, and the Government will make some framework for that. On the one hand, the Government is saying that the Regulatory Commissions are not functioning properly; on the other hand, in the name of the Regulatory Commission, the BJP Government is, again, allowing the rise in the power tariff in Delhi. It is not a good practice, especially because it is under the scrutiny of the High Court and the Supreme Court. If they have some respect for the verdict given to them by the people in the last elections, the Government will have to re-look into the matter. *(Time-bell rings)*

Atrocities against *dalits* in various States of the country

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में बहुत ही गंभीर इश्यू लाना चाहता हूं कि देश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। चाहे हम किसी भी प्रदेश की बात कर लें, आप एन.सी.आर.वी. से चैक कर सकते हो, हरियाणा प्रदेश में मिर्चपुर गांव में दलितों के घरों को जलाया गया था। अभी तक उनको अपने गांव में वापस भेजने की व्यवस्था तथा सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसी तरह से पंजाब में संगरूर जिले में बलदपुर गांव में जो जमीन की ऑक्शन होनी थी तथा इसमें दलितों का जो शेयर था, उन रूल्स का वॉयलेशन करके किसी और को देने के नजरिए से दलितों के ऊपर पुलिस का बेतहाशा तशद्दुद किया गया। उसमें 27.06.2014 को 97 नंबर एफ.आई.आर. दर्ज हुई। उसके तहत 41 निर्दोष दलितों को जेल भेज दिया गया और उस घटना में 15 दलित जख्मी हुए जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि यह जो गलत एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, सरकार इस पर विचार करके एफ.आई.आर. केंसिल करे। जिन 41 निर्दोष दलितों को बेवजह जेल में रखा गया है, उनको रिहा किया जाए और जो दलित जख्मी हैं, उन्हें कम्पनसेशन दिया जाए। साथ ही पंचायत की जमीन में जो उनका हक है, वह पंचायत की जमीन उन्हें दिलाई जाए। इसी तरह से फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के झखरवाल गांव में जिन दर्जनों दलितों के घरों को तोड़ा व जलाया गया है, उन्हें बेघर किया गया है, उन्हें भी कम्पनसेशन दिया जाए।

महोदय, पंजाब में दलितों पर बेतहाशा तशद्दुद अत्याचार हो रहे हैं, मुनकपुर तहसील के बाऊपुर गांव में अभी भी दलितों का बॉयकॉट चल रहा है। इसी तरह गांव नसोल, सुनाम तहसील व मलेरकोटला तहसील में भी उनका बॉयकॉट चल रहा है। इस अन्याय के विरुद्ध केन्द्र की सरकार वहां दखल दे।

महोदय, वहां अकाली दल व बी.जे.पी. की मिली-जुली सरकार है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि दलितों के साथ हो रहे अन्याय को रोका जाए। उनको इंसाफ मिले और उन्हें जमीन पर उनका हक दिलाया जाए तथा उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लिए जाएं। धन्यवाद।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं श्री करीमपुरी जी के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : महोदय, मैं श्री करीमपुरी जी के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री वी. हनुमंत राव (तेलंगाना) : महोदय, मैं श्री करीमपुरी जी के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं श्री करीमपुरी जी के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड) : महोदय, मैं श्री करीमपुरी जी के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री देरेक ओब्राईन (पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं श्री करीमपुरी जी के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं श्री करीमपुरी जी के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. The names of all those who have associated themselves may be added. Shri Tapan Kumar Sen.

Disinvestment of shares of profit-making public sector units by the Government

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I rise to draw the attention of the House towards the retrograde move of disinvestment of the shares of profit-making public sector units, a move which is going on as a part of policy measure to contain fiscal deficit.

Sir, I beg to say that the entire trade unions of the country-right, left and centre; all-have been opposing this, and they staged a two-day countrywide strike against this retrograde measure to bring the Government to*. Unfortunately, they are yet to succeed on that.

Sir, disinvestment, as we believe, at this moment, is not at all a prudent economic

*Expunged as ordered by the Chair.